भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1057

(जिसका उत्तर सोमवार, 08 फरवरी , 2021/19 माघ, 1942 (शक) को दिया जाना है)

फैक्ट्री उत्पादन में वृद्धि

1057. श्री असादुद्दीन ओवैसीः
श्री सय्यद ईम्त्याज जलीलः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अप्रैल 2020 में कम होकर 57.6 प्रतिशत तक रही फैक्ट्री उत्पादन वृद्धि, 3.6 प्रतिशत बढ़कर 8 मास से अधिकतम स्तर पर पहुंच गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सही है कि विनिर्माण, विद्युत, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं और गैर-टिकाऊ वस्तुओं ने मार्च से अक्तूबर तक गहरी आर्थिक मंदी के पश्चात सुधार दिखाया है;

(घ) यदि हां, तो संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए उत्पादन क्षेत्र को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अनुसार औद्योगिक उत्पादन में अप्रैल 2020 में (-) 57.3 प्रतिशत की बढ़त थी जो अक्तूबर 2020 में 4.2 प्रतिशत तक सुधरी और नवंबर 2020 में (-)1.9 प्रतिशत थी।

(ग) और (घ) विनिर्माण क्षेत्र में बढ़त मार्च 2020 में (-) 22.8 प्रतिशत से अक्तूबर 2020 में 4.1 प्रतिशत रही। इसी अवधि के दौरान विद्युत में बढ़त (-) 8.2 प्रतिशत से 11.2 प्रतिशत रही। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं और उपभोक्ता गैर-टिकाऊ मार्च 2020 में क्रमशः (-) 36.8 प्रतिशत और 22.3 प्रतिशत रही जो अक्तूबर-2020 में क्रमशः 18.0 प्रतिशत और 7.1 प्रतिशत रही।

(ङ) और (च) सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें 13 क्षेत्रों में सर्वोत्तम वैश्विक विनिर्माणों का सृजन करने हेतु उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन शुरू करना, खनिज क्षेत्र का वाणिज्यीकरण, श्रम सुधारों, एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन, संकटग्रस्त एमएसएमई हेतु कारोबारों और गौण ऋण के लिए संपार्श्विक निःशुल्क स्वचालित ऋण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन भारतीय कंपनियों से बढ़ाई गई सार्वजनिक खरीद संभव बनाने के लिए नियमों में परिवर्तन और एमएसएमई फंड ऑफ फंड्स के जरिए इक्विटी समावेशन से विनिर्माण क्षेत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत आरबीआई द्वारा किए गए उपायों सहित उत्प्रेणा और सुधार पैकेज लभगभ 27.1 लाख करोड़ रु. होने का अनुमान है जो जीडीपी के 13 प्रतिशत से भी अधिक है।

****